ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

तेजी से घट रही है ऊंटों की आबादी

रविवारीय, 27 सितंबर - 03 अक्टूबर 2020 वर्ष- दो, अंक-08, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं हवाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

झारखंड में पर्यटन स्थलों को संवारने में खर्च होंगें 52 करोड़ रूपये

रांची : झारखंड में पर्यटन स्थलों को संवारने और वहां सुविधाओं का उपलब्ध कराने के लिये 52 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। राज्य में पर्यटन को एक उद्योग के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने भी राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई है। जिसके तहत दलमा, नेतरहाट, बेतला जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को विकसित किया जायेगा। साथ ही झारखंड में चिन्हित किये गये अन्य पर्यटन स्थलों को भी संवारा जायेगा।

झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्य की भरमार है। हाल के कुछ सालों में इस ओर केंद्र और राज्य सरकार का भी ध्यान गया है और पर्यटन को एक उद्योग के तौर पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ साल पहले बॉलीवूड का ध्यान भी झारखंड के खुबसूरती की ओर आकृष्ट हुआ है और यहां कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है।

रांची टाटा मार्ग और हजारीबाग बरही मार्ग इनके निर्माण में हजारो पेड़ कटे अब स्मार्टसिटी के नाम पर रांची में 900 पेड़ कट रहे हैं यानि

विकास के नाम पर झारखंड में हरियाली की बर्बादी

मनोज कुमार शर्मा

रांची : पिछले ही साल राज्य सरकार की रिपोर्ट आयी थी कि झारखंड में वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है और अब यह बढ़ कर 32 प्रतिशत से कुछ ज्यादा है। यह आंकड़ा आम झारखंडियों को राहत दे सकता है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहां यह समझने की चीज है कि उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों में हरियाली बढ़ी है जिसमें राज्य में किसी भी प्रकार के वनों, पार्कों, बगीचों से लेकर खेतों में अरहर की फसल और केले के बगान को तक शामिल हैं लेकिन हरियाली के इतर राज्य में वास्तविक सघन वनों का प्रतिशत कितना बढा?

राज्य में हाइवे बनाने से लेकर अन्य निर्माणों में पुराने और विशाल वृक्षों की पुरजोर कटाई की गयी है। किसी भी सरकार की यह दलील होती है कि विकास के लिये यह आवश्यक है, लेकिन इसमें कभी भी अन्य विकल्पों पर विचार नहीं किया जाता है। बेशक राज्य के विकास के लिये सड़कों का होना आवश्यक है, पर क्या सड़क मार्ग परिवर्तित कर या समानांतर मार्ग बना कर सालों पुराने इन सुकूनदेह वृक्षों को काटने से बचाया नहीं जा सकता?

चित्र में रांची के धुर्वा में स्मार्टसिटी के निर्माण के नाम पर तकरीबन 300 पेड़ों को कटा हुआ देख सकते हैं। रांची में स्मार्टसिटी और स्मार्टरोड बनाने का प्रहसन बहुत पुराना है। ये दोनों चीजें दो दशकों में धरातल पर नहीं उतरीं, पर इनके नाम पर पुराने पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। धुर्वा में 900 पेड़ों को काटा जाना है, तकरीबन तीन सौ पेड़ों के कटने के बाद स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वृक्षों की कटाई रोक दी गयी है। लोगों का कहना है कि एचइसी के बनने के समय ही यह पेड़ इस इलाके में प्रदूषण को कम करने के लिये लगाये गये थे। ये पांच दशक पुराने पेड़ हैं जिन्हें हम कटने नहीं देंगे। लेकिन सरकार इसका कोई विकल्प नहीं खोज सकी और अंततः ये दशकों पुराने 900 पेड़ काट ही दिये जायेंगे।

हाल ही में एनजीटी ने झारखंड सरकार पर नये विधान सभा भवन क्लियरेंस लिये बगैर

बनाने पर 144 करोड़ का दंड लगाया है। इसके अलावा राज्य में कई ऐसे भवनों को भी चिन्हित किया गया है जो बिना एनजीटी के स्वीकृति के बनाये गये हैं। संभवतः झारखंड में एनजीटी का यह पहला सख्त कदम था। इसके बावजूद यहां सरकारें वनसंपदा संपन्न झारखंड में इनके संरक्षण को लेकर गंभीर नहीं रही है।

रांची जमशेदपुर मार्ग बनाने में अंधाधुंध काटे गये थे वर्षों पुराने पेड़

सालों से रांची जमशेदपुर मार्ग का निर्माण जारी है। इस सड़क के निर्माण में देरी भी एक मजाक बन कर रह गया है। इसमें विलंब पर कोर्ट तक ने टिप्पणी की और निर्माणकर्ता कंपनी को डांट फटकार तक लगायी गयी। लेकिन इस सड़क निर्माण का एक दुसरा पक्ष भी है कि इसके निर्माण के दरम्यान रांची से लेकर टाटा तक में सैकड़ो साल पुराने विशाल वृक्षों को काटा गया और उसकी लकड़ी तक गायब कर दी गयी। यह मामला समाचारपत्र से लेकर लोगों के द्वारा भी उठाया गया, पर मामले की लीपापोती कर दी गयी। करोड़ों की लकड़ियों का बंदरबाट हो गया। रांची जमशेदपुर मार्ग में काटे गये वृक्षों के बाबत जब वर्तमान सरकार के कद्दावर मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव से जब ग्रीन रिवोल्ट ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार जितना पेड़ निर्माण के दरम्यान कटेंगे उससे दुगुना पेड़ हम लगायेंगे।

हजारीबाग बरही सड़क से लेकर मंडल डैम निर्माण में भी बर्बाद हुये हैं सघन वन

पिछले साल हजारीबाग बरही तक सड़क निर्माण में हजारो पेड़ों को काटा गया था। इस दरम्यान सड़क बनाने वाली कंपनी को यह निर्देश था कि बचाये जा सकने वाले वृक्षों को उखाड़ कर शिफ्ट करना है, पर कंपनी ने इसका ख्याल नहीं रखा और अंधाधुंध हजारो पेड़ों को काट डाला गया। तब ग्रीन रिवोल्ट ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया था। पेड़ों की इस बर्बादी पर युवा एक्टिविस्ट संजय मेहता ने भी चिंता जाहीर की थी।

वैसे ही पलामू में मंडल डैम के निर्माण में भी हजारो विशाल वृक्ष डूब क्षेत्र में आ गये और उन्हे काटा गया।

यहां मूल विषय है कि, इन आवश्यक निर्माणों में पेड़ों का कटना मजबूरी है, पर क्या उसकी भरपाई उतने ही वृक्ष उन क्षेत्रों में लगा कर उसी क्षेत्र में की जाती है?

तैयार होते हैं दशकों में और धराशायी घंटों में

एक सघन वन क्षेत्र को तैयार होने में सालों लग जाते हैं। यह अपने आप में सभी जीवों के लिये एक अमूल्य संपदा है।इसलिये किसी निर्माण के लिये इसे काटने से पहले सभी विकल्पों पर ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि सैकड़ों सालों में तैयार हुआ एक वन कुछ ही घंटों में काट दिया जाता है और अगर उसके भरपाई में उतने ही वृक्ष लगा भी दिये जायें तो उन वृक्षों को बचते बचाते फिर से तैयार होने में दशकों लग जाते हैं। इस तरह उस क्षेत्र में पर्यावरण को हुये नुकसान की भरपाई संभव नहीं हो पाती।

वज्रकीट के साथ चार तस्कर धराये

रांची : तमाड़ थाना क्षेत्र में चार लोगों को पुलिस ने वज्रकीट के साथ पकड़ा है। चारो व्यक्ति वज्रकीट को छुपा कर रखे हुये थे और किसी अच्छी कीमत देने वाले को इसे बेचने की फिराक में थे। वज्रकीट को ही पैंगोलीन कहते हैं। यह चीटियों और दीमकों को खाता है।

पकड़े गये चारो तस्करों ने बताया कि इस पैंगोलीन की उन्हें कोई खरीददार दस लाख रूपये दे रहा था, पर ज्यादा पैसे के लालच में उन्होंने अब तक इसे नहींबेचा था और छुपा कर रखे हुये थे।

झारखंड में अक्सर वज्रकीट मिलते हैं और ग्रामीणों की नजर पड़ने पर इन्हें पकड़ कर वन विभाग को सौंप दिया जाता है। यह मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। कुछ दिनों पहले रांची के पिठौरिया इलाके में भी ग्रामीणों ने एक वज्रकीट पकड़ा था जिसे वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया गया था। वज्रकीट के शरीर पर कड़े शल्क होते हैं और इसी शल्क के लालच में इसे पकड़ कर वन्यजीव तस्करी के लिये बेचा जाता है। इस कड़े शल्क से विदेशों में किसी औषधी बनाने का दावा किया जाता है।

रांची विवि के राष्ट्रीय सेवा योजना का फिट इंडिया मूवमेंट

रांची विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट के तहत बुधवार को शहीद चौक स्थित विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के विश्वविद्यालय कार्यक्रम समन्वयक डॉ. ब्रजेश कुमार ने स्वयंसेवकों को स्वच्छता अपनाने और इसके प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरित किया। इसमें एनएसएस के टीम लीडर- दिवाकर आनंद, सुमित तिवारी, शुभम चौधरी, अंजलि कुजूर, अन्नू कुमारी, दीपा कुमारी, निकिता सुमन, नवीन किशोर, शालू जायसवाल, जमील, फलक फातिमा, सुरेश, सूरज, धिरंजन, केशव आदि का योगदान रहा। अभियान में 9 कॉलेज, तीन स्नातकोत्तर विभागों के कुल 49 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया।

बड़ा तालाब से हटेगा अतिक्रमण बड़े वाहनों के पार्किंग पर भी रोक

संवाददाता

रांची : हाईकोर्ट के सख्त रूख के बाद नगरआयुक्त समेत कई अफसरों ने बड़ा तालाब का मुआयना किया और अब एसडीओ को कहा गया है कि तालाब के इलाके का सीमांकन करवायें। साथ ही यह पता करें कि इसके कितने इलाके पर अतिक्रमण है। इसके लिये अमीनों की एक टीम बनायी जा रही है जो मापी कर तालाब के इलाके को चिन्हित करेगी। साथ ही तालाब में प्रदूषण का स्त्रोत क्या है? और इसमें कितने नाले बहाये जा रहे हैं इस बात की भी जानकारी एकत्र की जायेगी। बड़े वाहनों के पार्किंग पर भी अब रोक लगा दी गयी है।

ज्ञात हो कि 1844 में कर्नल ओंस्ले के द्वारा यह गोलाकार झील रांची की कभी शान हुआ करती थी। जानकार बताते हैं कि इस तालाब को कैदियों के द्वारा खुदाई कर बनवाया गया था। इसमें तीन टापू हैं। इसके सौंदर्यीकरण की कवायद दशकों से चल रही है। लेकिन बड़ा तालाब आज भी जलकुंभी और प्रदूषण का शिकार है। पहले इसके किनारों पर पोल्ट्री दूकानें भी थीं साथ ही फल मंडी के कचड़ों को भी यहीं डंप कर दिया जाता था। इससे सटे एक बड़े अस्पताल का कचड़ा एवं नाला भी बड़ा तालाब में ही बहाया जाता है।

इसके बीच वाले टापू पर विवेकानंद की विशाल मूर्ति स्थापित कर इसका नाम स्वामी विवेकानंद सरोवर रख दिया गया साथ ही इस टापू पर पहुंचने के लिये एक पुल भी बना दिया गया, पर झील की गंदगी और जलकुंभी हटाने का काम हमेंशा ठंढे बस्ते में रहा। बड़ा तालाब कभी भी स्वच्छ नहीं हो पाया। इसके किनारे की चारदिवारी से इसमें जलसंचयन भी बाधित हो गया है।

सीएमपीडीआई कोल इंडिया का अभिन्न हिस्सा, इसे अलग नहीं किया जायेगा

रांची : सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) कोल इंडिया का अभिन्न हिस्सा है और इसे उससे अलग नहीं किया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी सीएमपीडीआईएल के पास भू-संरचनात्मक जटिलताओं के रहते हुए भी खनन परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत अनुभव है। सीएमपीडीआई ने प्रतिवर्ष 500 मिलियन टन से अधिक कोयले की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के लिए लगभग 700 परियोजनाओं की योजना बनाई है। इसने खानों की पुनर्संरचना में, भूमिगत खदानों को खुली खदानों में परिवर्तित करने में तथा उबड़-खाबड़ भू-भागों इत्यादि के खनन में महारत हासिल की है। ये बातें सुनिल कुमार विभागाध्यक्ष पीआर एवं सीसी कोल इंडिया ने कही।

उन्होंने कहा कि सीएमपीडीआईएल कोयला उत्पादक इकाइयों के लिये योजना और दिशानिर्देश तैयार करने का कार्य करती है और वित्तीय वर्ष 2023-24 तक एक बिलियन टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका होगी। कंपनी की परामर्श इकाई सीएमपीडीआई ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7.8 बिलियन टन कोयला उत्पादन में सहायक सिद्ध हुआ था। कुल 25 भूगर्भीय रिपोर्ट की तैयारी के माध्यम से292 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत खोज के बाद यह संभव हो पाया था।

कोयला के अतिरिक्त सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया की पर्यावरण अनुकूल एवं मशीनकृत तरीके से कोयले के रखरखाव और उसके गंतव्य तक भेजने की 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी' परियोजनाओं में तकनीकी परामर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

2020-21 में सामान्य से अधिक होगी फसलों की पैदावार

एजेंसियां :खरीफ 2020-21 के दौरान कृषि वर्ष 2020-21 के लिए अधिकांश फसलों का उत्पादन उनके सामान्य उत्पादन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। खरीफ सीजन 2020-21 के पहले अनुमान में 102.36 मिलियन टन चावल के उत्पादन की बात कही गई है।

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 2020-21 की प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए हैं। अनुमान है कि खरीफ सीजन में देश में कुल 144.52 मिलियन (14.45 करोड़) टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा। विभाग ने इस उत्पादन को रिकॉर्ड बताया है। विभाग का कहना है कि 2020-21 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन 102.36 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2018-19 में खरीफ सीजन में 102.04 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ था।

विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक इस वर्ष के दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम के दौरान 16 सितंबर, 2020 तक संचयी वर्षा दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) से 7 प्रतिशत अधिक रही। इसके चलते अधिकांश प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों में सामान्य वर्षा देखी गई है। कृषि वर्ष 2020-21 के लिए अधिकांश फसलों का उत्पादन उनके सामान्य उत्पादन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, ये अनुमान राज्यों से आगे मिलने वाली जानकारी के आधार पर संशोधित होंगे।

2020-21 के लिए पहले अग्रिम अनुमानों (केवल खरीफ) के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 144.52 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2020-21 के दौरान उत्पादन पिछले पांच वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन (2014-15 से 2018-19) के मुकाबले 9.83 मिलियन टन अधिक है। 2020-21 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन 102.36 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन 95.66 मिलियन टन की तुलना में 6.70 मिलियन टन अधिक है।पोषक तत्वों / मोटे अनाजों का उत्पादन 32.84 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 31.39 मिलियन टन के औसत उत्पादन की तुलना में 1.45 मिलियन टन अधिक है।

2020-21 के दौरान कुल खरीफ दालों का उत्पादन 9.31 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह 2019-20 (चौथे अग्रिम अनुमान) में 7.72 मिलियन टन दालों के उत्पादन की तुलना में 1.59 मिलियन टन अधिक है।

देश में 2020-21 के दौरान कुल खरीफ तिलहन उत्पादन 25.73 मिलियन टन होने का अनुमान है जो 2019-20 के दौरान उत्पादन की तुलना में 3.41 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा, 2020-21 के दौरान तिलहन का उत्पादन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 5.90 मिलियन टन अधिक है।

देश में 2020-21 के दौरान गन्ने का कुल उत्पादन 399.83 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2020-21 के दौरान गन्ने का उत्पादन औसतन 360.43 मिलियन टन गन्ने के उत्पादन की तुलना में 39.40 मिलियन टन अधिक है।

कपास का उत्पादन 37.12 मिलियन गांठ (प्रत्येक 170 किलो) अनुमानित है, 2019-20 के दौरान 35.49 मिलियन गांठ के उत्पादन की तुलना में 1.63 मिलियन गांठ अधिक है। जूट और मेस्टा का उत्पादन 9.66 मिलियन गांठ (प्रत्येक 180 किलोग्राम) होने का अनुमान है।

बोत्सवाना में 350 हाथियों की मौत का कारण पता चला

सुधीर सिंह

तीन महीने पहले हाथियों के गढ़ माने जाने वाले दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में 350 से अधिक हाथियों की मौत की ख़बर आई थी। उस समय किसी को नहीं पता कि इतनी बड़ी संख्या में हाथियों की मौत का कारण क्या है.मगर अब इन हाथियों की मौत का कारण पता चल गया है। बताया जा रहा है कि पानी में मौजूद साइनोबैक्टीरिया के कारण हाथियों की मौत हुई।

2 जुलाई के आसपास बोत्सवाना के जंगलों में सैकड़ों हाथियों की लाशें देखने को मिली थीं, जिसके बाद से ही बोत्सवाना की सरकार हाथियों की रहस्यमयी मौत का पता लगाने में जुट गई थी.इस मामले पर उस समय डॉयरेक्टर ऑफ कंजर्वेशन एट नेशनल पार्क रेस्क्यू डॉक्टर नील मैकेन ने गार्जियन से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में इससे पहले प्राकृतिक रूप से हाथियों को मरते हुए कभी नहीं देखा. ऐसी मौत सिर्फ सूखे के दौरान होती है, लेकिन अभी तो पानी मौजूद है. उन्होंने सरकार द्वारा लैब टेस्ट के नतीजे का इंतजार करने की सलाह दी थी. सोशल मीडिया पर इस मामले पर खूब चर्चा हुई थी.जुलाई महीने में हाथियों की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें जंगल में चारों तरफ हाथियों की लाशें ही लाशें देखी गई थी. ध्यान देने वाली बात यह है कि हाथियों की इस रहस्यमयी मौत का पहला मामला मई में सामने आया था. आगे यह सिलसिला चलता रहा और जून के अंत तक हाथियों की मौत का आंकड़ा 350 को पार कर गया था.

डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्डलाइफ एंड नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर सिरिल ताओलो के मुताबिक उत्तरी बोत्सवाना और उसके ओकावैंगो डेल्टा में 350 से ज्यादा हाथियों के सड़े-गले शव बिखरे थे. हाथी की

पानी में मौजूद साइनोबैक्टीरिया के कारण हाथियों की मौत हुई

पहली रहस्यमयी मौत मई महीने में हुई थी. उसके बाद कुछ दिनों के अंदर ओकवैंगो डेल्टा में 169 हाथी मर गए. जून के मध्य तक हाथियों के मरने की संख्या लगभग दोगुनी हो गई. इनमें से 70 फीसदी हाथियों की मौत जलस्रोतों के आसपास हुई थी.सिरिल ने बताया कि जांच में पता चला है कि पानी में साइनोबैक्टीरिया थे. जिनकी वजह से पैदा हुए जहर से हाथियों की मौत हुई है. कारण कुछ भी हो मगर, इस तरह से हाथियों का मरना चिंताजनक है.

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

संपादकीय

झारखंड में झीलों तालाबों को बचाने का प्रहसन

हाल ही में किसी पर्यावरण प्रेमी ने रांची के बड़ा तालाब को बचाने के लिये एक जनहित याचिका दायर किया है। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और इसे बचाने, संवारने का आदेश सुना दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई बार रांची के जलाशयों , डैमों के प्रदूषण पर कोर्ट ने संज्ञान लिया, अफसरों और सरकार को लताड़ लगायी, खबरें छपीं लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रही।

कुछ साल पहले कांके डैम के प्रदूषित जल की शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट में डैम का पानी बोतल में मंगवाया गया। जज साहब प्रदूषित बदबूदार जल को देख कर भड़क गये, संबंधित अधिकारी को सबों के बीच फटकार लगायी और कहा कि गनीमत समझिये कि आप को ये पानी पीने को नही कह रहे हैं। तब इस ख़बर ने ख़ूब सुर्ख़ियां बटोरी थी।

ठिक ऐसे ही रांची के प्रदूषित बड़ा तालाब से मछली मार कर खाने से एक युवक की मौत हो गयी थी। आज इन वाकयों के दशकों बाद भी रांची के इन दोनों तालाबों की हालत जस की तस है। अब सरकार तालाबों से जलकुंभी हटाने वाली मशीनें ख़रीद रही है, पर प्रदूषण, अतिक्रमण रोकने के साथ ही इन झीलों में जल कैसे एकत्र हो इसपर भी ध्यान देना होगा।

कुछ साल पहले कांके डैम के कैचमेंट में बने मकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। तब कई लोगों ने इसे अमानवीय करार दिया था। लेकिन इतने सालों में डैम के आस पास फिर से अवैध मकान बने हैं, इसकी जमीन कब्जाई गयी है। इनमें कई मकान अमीरों और रसूखदारों के हैं इनके तोड़ने की चर्चा भी होती है, पर क्या ये संभव है? पिछला रिकार्ड तो यहीं कह रहा है कि यहां से बड़े मकानों को हटाने की बात करना सिर्फ बयानबाजी है।

वैसे ही रांची झील जिसे बड़ा तालाब या विवेकानंद सरोवर कहते हैं उसे सजाने संवारने का मजाक तो दशकों से चल रहा है , लेकिन यह झील आज तक ज्यों का त्यों जलकुंभी और प्रदूषित जल के साथ पूरे सिस्टम को मुंह चिढा रहा है।

धुर्वा डैम के किनारे रिंग रोड को इस तरह से बनाया गया है कि अब बरसात का पानी डैम में एकत्र होने के बजाय किसानों के खेतों में फसलों को डूबो रहा है और डैम पर्याप्त बारिश के बाद भी खाली रह जा रहा है। रांची की आबादी पानी के लिये आस पास के बड़े जलाशयों जैसे धुर्वा डैम, रूक्का डैम, कांके डैम पर ही आश्रित है और इन जलाशयों का ऐसा हश्र? आखिर यह आत्मघाती प्रहसन नहीं तो और क्या है?

आगरा में पक्षी विहार में हो रहा था अवैध निर्माण, एनजीटी ने दिए जांच के आदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 18 सितंबर को निर्देश दिया कि सूर स-रोवर पक्षी विहार, आगरा, उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए। इस समिति में मुख्य वन्यजीव प्रबंधक, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन प्रभाग के सदस्य शामिल होंगे। एनजीटी के समक्ष दायर एक याचिका में कहा गया है कि हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (एचआईटी) और आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज (एईसी) सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, जिला आगरा के भीतर हैं।

न्यायालय ने उल्लेख किया कि यद्यपि अभयारण्य के मानचित्र में संरक्षित क्षेत्र 403.09 हेक्टेयर था, अभयारण्य का क्षेत्रफल 1020.25 हेक्टेयर था। 403.09 हेक्टेयर के बाहर निर्माण हैं लेकिन यह 1020.25 हेक्टेयर के भीतर है। यदि वे वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा थे, तो वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 27 के तहत, ऐसे निर्माणों की अनुमति नहीं थी और वे तब तक अवैध थे जब तक कि वन्य जीवन अभयारण्य की सीमा अधिनियम की धारा 26 ए के तहत बदल न दी गई हो। निर्माण 1991 की अधिसूचना के बाद होने की बात कही गई थी। इस प्रकार या तो यह स्पष्ट रूप से घोषित किया जाना चाहिए कि यह क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। ऐसे में उक्त क्षेत्र के सभी निर्माणों को हटा दिया जाना चाहिए या वन्यजीव अभयारण्य की सीमा को उचित रूप से सीमांकित और निर्धारित किया जाना चाहिए।

डिजिटल ही सही, संपन्न हुआ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन डे

साल 2020 खत्म होने से पहले ही ऐतिहासिक बन चुका है। और इस ऐतिहासिक साल में एक यादगार दिन सितम्बर 25 रहा जिसे याद किया जायेगा ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन डे के नाम से। इस दिन, कोविड-19 के मद्देनज़र सभी सावधानियों बरतते हुए, दुनिया भर में फ्राइडे फॉर फ्यूचर के बैनर तले स्कूल हड़ताल आंदोलन होगा और दुनिया भर में बेहतर जलवायु की मांग रखते हुए प्रदर्शन हुये।

लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान, कोविड-19 महामारी ने कार्यकर्ताओं और आंदोलनकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन के नए तरीके खोजने पर मजबूर कर दिया है। आखिर अब पैदल मार्च और भीड़ का हिस्सा बनना जनहित में सुरक्षित जो नहीं। और इसी क्रम में जलवायु परिवर्तन के ख़िलाफ़ इस आन्दोलन ने डिजिटल अवतार धारण कर लिया है। कल, मतलब 25 सितंबर को इस साल का पहला ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन डे होगा। अपना बयान जारी करते हुए फ्राइडे फॉर फ्यूचर ने कहा कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि पेरिस एग्रीमेंट के समझौते के तहत ग्लोबल मीन तापमान को 1.5C से कम रखना आगामी माह और सालों मे कठिन होगा। स्थिति मानव नियंत्रण से बाहर न हो इसके लिए अभी से क़दम उठाने होंगे। कोविड-19 के आगे जलवायु संकट छोटा नहीं हुआ है बल्कि यह वक़्त तो इसे प्राथमिकता देने का है। जब तक प्रकृति का दोहन होता रहेगा तब तक फ़्राइडे फ़ॉर फ्यूचर अपने आन्दोलन जारी रखेगा। चाहें सशरीर हो प्रदर्शन, या डिजिटल-लेकिन विरोध प्रदर्शन होगा ज़रूर कोविड-19 की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए। इस आन्दोलन पर फ्राइडे फ़ॉर फ्यूचर ,केन्या, के एरिक डेमिन कहते हैं, ''महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनेताओं के पास विज्ञान की मदद से शीघ्र और स्थायी क़दम उठाने की शक्ति है। लेकिन महामारी के दौरान भी जलवायु संकट पर लगाम नहीं लग पा रही है। स्थायी और न्यायपूर्ण तरीके से दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। अब महामारी से निपटने के लिए किए जाने वाले अरबों-डॉलर के निवेश पेरिस समझौते के अनुरूप होने चाहिए।

एरिक की बात आगे ले जाते हुए फ्राइडेज़ फ़ॉर फ्यूचर, भारत, से दिशा रवि कहती हैं, ''समस्या की गंभीरता तब समझ आती है जब अपने पर गुज़रती है। लाखों लोग अपना घर और जीवन यापन की आवश्यक चीजें खो रहे हैं। इसे अनसुना नहीं किया जा सकता। हमें ऐसे वैश्विक राजनेताओं की जरुरत है जो लालच की जगह मानवता को प्राथमिकता दें। अच्छी बात यह है कि अब युवा वर्ग पहले से ज़्यादा योजनाबद्ध और संगठित तरीक़े से संगठित हो रहा है। हो सकता है वर्तमान परिस्थितियों के चलते उठाए जा रहे क़दम वैसे न हों जैसे हो सकते थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया भर के युवा अब आवाज़ उठा रहे हैं एक बेहतर कल के लिए जहाँ हमारी आने वाली नस्लें बेहतर जीवन जी सकें।

आर्कटिक को खोना भयंकर क्षति होगी: विशेषज्ञ

24 सितंबर को, संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च-स्तरीय जलवायु शिखर सम्मेलन के 75-वें समिट से पहले, यूके क्लाइमेट चैंपियन नाइजिल टॉपिंग के साथ आर्कटिक वैज्ञानिकों के एक समूह ने आर्कटिक बर्फ के पिघलने से होने वाले नुकसान के मतलब समझाए। कैसे यह दिन-ब-दिन बत्तर होते जलवायु के प्रभावों की दास्तान बयान करते हैं । अध्ययन बताते हैं कि आर्कटिक को खोना हमें बड़ा महंगा पड़ेगा और ऐसा होना हमारे लिए दुखद खबर होगी। जहाँ एक ही सप्ताह में एक तरफ कैलिफोर्निया की वाइल्डफायर विनाश का रास्ता जला रहीं हैं और दुसरे तरफ ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का हिस्सा अलग हो गया है। यह साइबेरिया में तपती गर्मी, गर्मियों की शुरुआत में कनाडा के आइस शेल्फ के नुकसान, आदि सब इसका ह्रभावों का हिससा हैं। यह असंबंधित लगने वाली घटनाएँ असल में जुड़े हुई हैं, और जितना संभव हो उतना आर्कटिक समुद्री बर्फ और बर्फ की चादरों को बचाना हमें भविष्य के लिए सबसे सर्वोत्तम मौका देता है।

क्लाइमेट रिसर्च सेंटर के डॉ जेनिफर फ्रांसिस वुडवेल, के अनुसार-आर्कटिक बहुत तेजी से बदल रहा है और गर्म हो रहा है। आर्कटिक की बर्फ और हिम (स्नो), जो सूरज से गर्मी को दर्शाते हैं, को खोने से हम पृथ्वी को अँधेरे में डाल रहें है और ग्लोबल वार्मिंग के मौजूदा प्रभावों को कम से कम 25% तक बत्तर कर रहे हैं। यह अतिरिक्त वार्मिंग समुद्र के स्तर में वृद्धि को तेज करती है, और वायुमंडल में अतिरिक्त कार्बन और मीथेन को जारी करते हुए, परमाफ्रॉस्ट थौ/पिघल को गति देती है। तेज़ आर्कटिक वार्मिंग ठंडी उत्तर और गर्म दक्षिण के बीच तापमान के अंतर को भी कम करती है। यह तापमान अंतर जेट स्ट्रीम को तेज़ करता है, हवा की एक तेज़ नदी जो उत्तरी गोलार्ध के चारों ओर मौसम का निर्माण और स्टीयरिंग करती है। एक छोटे तापमान के अंतर का अर्थ है कमजोर जेट-स्ट्रीम पश्चिमी हवाएं, जिसके कारण मौसम के रुख स्थिर हो जाते हैं, और लंबे समय तक रहने वाली मौसम की स्थिति जैसे सूखा, गर्मी की लहरें, ठंड की लहरें और तूफ़ानी अवधि बन जाती है। मौसम से संबंधित चरम घटनाओं की आवृत्ति केवल 40 वर्षों की छोटी अवधि में तीन गुना हो गई है। हम ये और बिगड़ते देखेंगे क्योंकि बर्फ तेज़ी से पिघलती रहेगी।

प्रोफेसर जुलिएन स्ट्रोव, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन कहती है कि ग्रीनहाउस गैसों से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग से पड़ने वाली भीषण गर्मी दुनिया की तबाही के ताबूत में एक और कील ठोकती है। समय के साथ हम उत्सर्जन को ट्रैक कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि आर्कटिक समुद्री बर्फ को पिघलाने के लिए प्रत्येक देश कितना जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए 2019 में, चीन 30,000 वर्ग किलोमीटर, और अमेरिका 14,400 वर्ग किलोमीटर, समुद्री बर्फ के नुकसान के लिए जिम्मेदार थे। यह पिघलाव अभी भी वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि में योगदान दे रहा है।

नाइजेल टॉपिंग, COP26 के लिए यूके हाई लेवल क्लाइमेट एक्शन चैंपियन ने कहा कि हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां जलवायु परिवर्तन के प्रभाव यहां और अभी वास्तव में मौजूद हैं। 1.5 पर IPCC की विशेष रिपोर्ट ने समाज के सभी हिस्सों पर दिल दहलाने वाला जिस प्रभाव का जिक्र किया था वह आज सच होता नजर आ रहा है । एक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण है । हर देश के नेताओं को विज्ञान को गंभीरता से लेना चाहिए और अगले पांच से दस वर्षों में इस परिवर्तन को लेन की आवश्यकता है ताकि हम पेरिस के लक्ष्यों तक पहुंच सकें। लेकिन हमें उन प्रभावों को भी अपनाने की जरूरत है जिनसे हमने खुद को पहले से बाँध लिया है। नवंबर 2021 से पहले सरकारों और व्यवसायों और शहरों द्वारा किया गया प्रयास, COP26 जितना ही महत्वपूर्ण है। COP26 एक क्रैसेन्डो होना चाहिए, न कि एकमात्र क्षण जहां हम सरकारों से महत्वाकांक्षा, प्रतिज्ञा और परिवर्तन देखते हैं।

प्रोफेसर गेल वाइटमैन, एक्सेटर बिजनेस स्कूल के विश्वविद्यालय और आर्कटिक बेसकैंप संस्थापक ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि : पूरी दुनिया मैक्रोन के साथ खड़ी थी जब इस खबर के जवाब में कि अमेरिका पेरिस समझौते से पीछे हट रहा है।

डॉ. जेनिफर फ्रांसिस वुडवेल, क्लाइमेट रिसर्च सेंटर - आर्कटिक और नए जीवाश्म ईंधन बुनियादी ढांचे में प्रस्तावित एलएनजी पाइपलाइन पर प्रतिक्रिया: जब आप चरम घटनाओं और जलवायु प्रभावों की बड़ी तस्वीर देखते हैं, तो हम पहले से ही से थोड़े अधिक का सामना कर रहे हैं, और आर्कटिक में प्रस्तावित एलएनजी पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं पर खर्च किए गए संसाधन और जीवाश्म ईंधन का समर्थन करने के लिए किसी भी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना गलत दिशा में जा रहा प्रोफेसर जुलिएन स्ट्रोव, मैनिटोबा विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन - विज्ञान आर्कटिक ने एक टिपिंग पॉइंट पार करने के विचार पर कहा कि हमने अगली आईपीसीसी रिपोर्ट के लिए शोध प्रस्तुत किया है जो दर्शाता है कि हम भविष्य के उत्सर्जन परिदृश्य के तहत गर्मियों में समुद्री बर्फ खो देंगे। लेकिन जितना संभव हो उतना संरक्षित और मरम्मत करना मुमकिन है। हमें न केवल शमन करने में, बल्कि वातावरण से कार्बन हटाने और बाद में जल्द से जल्द अभिनव करने की आवश्यकता है। डॉ। जेनिफर फ्रांसिस वुडवेल, क्लाइमेट रिसर्च सेंटर - लोग और सरकारें इस विचार पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं कि आर्कटिक ने एक टिपिंग पॉइंट पार कर लिया है: एक टिपिंग पॉइंट का अर्थ है कि हम एक चट्टान से गिर जाते हैं और वापस ऊपर नहीं चढ़ सकते। लेकिन वास्तव में यह एक निरंतर परिवर्तन है। लोग पहचानने लगे हैं कि उनके अपने मोहल्ले उन तरीकों से बदल रहे हैं जिनके साथ उनका कोई अनुभव नहीं है। लोग जानते हैं कि चीजें सामान्य नहीं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां रहते हैं, चाहे आप इस वर्ष अधिक ट्रॉपिकल/उष्णकटिबंधीय तूफान का सामना कर रहे हैं, या सूखे और गर्मी के परिणामस्वरूप होने वाली आग को देखते हुए, ये सब प्रभाव आर्कटिक में बदलावों से प्रभावित हैं। और जब तक हम इसे उलट नहीं सकते, पर हम परिवर्तनों की गंभीरता को कम कर सकते हैं।

निशांत सक्सेना द्वारा प्रेषित

ओलम्पिक खिलाड़ियों की जलवायु परिवर्तन पर चिंता

ओलम्पिक खिलाड़ियों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये लिखा पत्र

ब्रिटेन के 300 से ज्यादा ओलम्पियन और पैरालम्पियन खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पत्र लिखकर कोविड-19 संकट के मद्देनजर जलवायु परिवर्तन को लेकर फौरी कदम उठाने का आह्वान किया है।

यह खत जीबी रोविंग टीम की सदस्य और पर्यावरण से जुड़े मामलों की पैरोकार मेलिसा विल्सन द्वारा चैम्पियंस फॉर अर्थ की ओर से लिखा गया है। मेलिसा ने इस पत्र को ओलम्पिक और पैरालम्पिक एथलीट्स के साथ पिछले अगस्त में साझा किया था। यह खत बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचा और ब्रिटेन के 300 से ज्यादा नामी एथलीट्स ने इस पर दस्तखत किये। इनमें 40 ओलम्पिक और पैरालम्पिक चैम्पियन भी शामिल हैं। मेलिसा ने महसूस किया कि कोविड-19 ने बदलाव के लिये बहुत बड़ा अवसर मुहैया कराया है, लिहाजा उन्होंने यह खत लिखने का फैसला किया।

मेलिसा ने कहा ''अपनी नौजवान पीढ़ी के लिये पर्यावरण को बचाने का यह ऐसा मौका है जो जिंदगी में एक ही बार मिलता है। महामारी से उबरने की मजबूरी हमें अपनी हवा को साफ करने का मौका दे रही है। खासतौर से उस युवा वर्ग के भले के लिये हमें यह मौका लपक लेना चाहिये जिनके फेफड़े वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ओलम्पिक और पैरालम्पिक एथलीट होने के नाते हम वैश्विक समुदाय के रूप में एकजुट होकर काम करने की ताकत को समझते हैं। अगले साल आयोजित होने जा रहे सीओपी26 के मद्देनजर हमारा मानना है कि ब्रिटिश सरकार के पास इस मुद्दे को लेकर दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाने और यह दिखाने का सुनहरा मौका है कि इस मसले पर और क्या किया जा सकता है।

ब्रिटेन अगले नवम्बर में ग्लासगो में आयोजित होने जा रही सीओपी26 यूएन क्लाइमेट समिट की मेजबानी करेगा। उम्मीद है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में दुनिया के विभिन्न सदस्य देश ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने, वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को बचाने की योजनाओं की नयी श्रंखला पेश करेंगे। कोविड-19 के कारण दुनिया में हुए लॉकडाउन के दौरान वैश्विक उत्सर्जन से कुछ राहत मिलने के बावजूद यूएन के वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरनाक प्रभाव लगातार बदतर होते जा रहे हैं।

पांच बार के ओलम्पिक चैम्पियन स्टीव रेडग्रेव- "एक एथलीट के रूप में सर्वोच्च स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिये आपको स्वस्थ पर्यावरण की जरूरत होती है। यह बहुत जरूरी है कि ब्रिटेन के बच्चे साफ हवा में सांस लेते हुए बड़े हों, हरे-भरे माहौल में जियें और स्वास्थ्यवर्द्धक खुराक लें। ब्रिटेन हमेशा से अग्रणी भूमिका में रहा है और यह जरूरी है कि यह देश भविष्य के सितारों को फलने-फूलने का मौका देने के लिये सुरक्षित पर्यावरण मुहैया कराने में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाये। डबल ओलम्पिक चैम्पियन रेबेका एडलिंग्टन ओबीई- ''तैराकी बचपन से ही मेरा जुनून रही है, लेकिन हम लगातार यह देख रहे हैं कि हमारे समुद्र प्रदूषित और शोषित-दोहित होते जा रहे हैं। वर्ष 2012 की तरह ब्रिटिश नेतृत्व एक ऐसी सफल वैश्विक यूएन क्लाइमेट समिट का आयोजन कर सकता है जो भावी पीढ़ियों के लिये एक मिसाल बनेगी। हमें अच्छे भविष्य के लिये अभी काम करना होगा।

डबल ओलम्पिक चैम्पियन एलिस्टेयर ब्राउनली एमबीई- ''एक ट्राइएथलीट के तौर पर मैं टोक्यो ओलम्पिक्स -2021 के लिये बेहद सख्त गर्मी में ट्रेनिंग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि ऐसे मुश्किल हालात में प्रदर्शन करना कितना दुश्वारी भरा है। मुझे प्रतिस्पर्द्धा पसंद है लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि आने वाले वक्त में मेरा खेल भावी पीढ़ियों की सेहत के लिहाज से सुरक्षित हो। यही वजह है कि मैं चाहता हूं कि सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने में अग्रणी भूमिका निभाये।चार बार की ओलम्पियन और मैराथन विश्व रिकॉर्डधारी (2003-2019) पाउला रैडक्लिफ एमबीई- "वायु प्रदूषण का कोई भी स्तर सुरक्षित नहीं है। हम सभी को और कोशिश करनी होगी और सरकार को नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने की जरूरत है। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली सीओपी26 समिट ब्रिटेन के लिये एनवॉयरमेंट ओलम्पिक्स होगी- मगर यह एक मैराथन दौड़ है, फर्राटा दौड़ नहीं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह इसके लिये तैयार है और उसके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिये जरूरी नीतियां मौजूद हैं।

टोक्यो ओलम्पिक 1964 की चैम्पियन लेडी मैरी पीटर्स एनजी सीएच डबीई डीएसटीजे- ''कृपया हमारी धरती का सेहत भरा भविष्य सुनिश्चित करें। अभी कोशिश करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ब्रिटिश ओलम्पिक एसोसिएशन की उपाध्यक्ष अन्नामेरी फेल्प्स सीबीई ने कहा अपने बच्चों और भविष्य की अन्य पीढ़ियों के लिये एक सतत और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से ज्यादा और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मेलबर्न ओलम्पिक 1956 की चैम्पियन जूडी ग्रिनहम एमबीई ने कहा ''वाकई कुछ न कुछ तो करने की जरूरत है। मेरी उम्र 81 साल है और मैं अपने बच्चों और नाती-पोतों के लिये अच्छा भविष्य बनाना चाहती हूं। ओलम्पियन होने के नाते मैं महसूस करती हूं कि दुनिया को अधिक सुरक्षित और बेहतर जगह बनाने के लिये निर्णायक कदम उठाने की अपील के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी ने यह जाहिर किया है कि हम सभी साथ मिलकर मुश्किल हालात से बाहर निकल सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरा समर्थन सरकार का ध्यान खींचने में मदद करेगा, ताकि हमारे सभी बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिये निर्णायक कदम उठाये जा सकें।

भारतीय खगोलविदों ने 70 नए परिवर्तनशील सितारों की खोज की

भारत के खगोलविदों ने एनजीसी 559 नामक तारामंडल का लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद 70 नए परिवर्तनशील सितारों का पता लगाया है। तारों का समूह नक्षत्रीय विकास का अध्ययन करने के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि वे समान गुणों वाले सितारों का संग्रह होता हैं। उनकी आयु, दूरी और प्रारंभिक संरचना एक जैसी होती है।

खगोलविद अक्सर युवा और मध्यवर्ती उम्र के समूहों में परिवर्तनशील सितारों की खोज करते हैं, जो पूर्व मुख्य अनुक्रम (पीएमएस) सितारों की समझ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकता है।

पृथ्वी से लगभग 7,900 प्र-काश वर्ष की दूरी पर स्थित एनजीसी 559 लगभग 22.4 करोड़ वर्ष पुराना एक खुला समूह है। एनजीसी 559 के पिछले अवलोकन में 542 सितारों की पहचान की गई थी अब भारत में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज (एआरआ-ईईएस) के योगेश सी जोशी के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने एनजीसी 559 के लंबे समय तक प्रकाश को मापने (फोटोमेट्रिक) के परिणामों को प्रकाशित किया है। उन्होंने भारत में स्थित अलग-अलग 1 से 2 मीटर वर्ग की दूरबीनों का उपयोग किया। तीन वर्षों से अधिक समय तक चले इस अवलोकन के परिणामस्वरूप एनजीसी 559 में दर्जनों नए परिवर्तनशील तारों की खोज हुई। खोज अरक्षिव नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई है।

मंडी जिले में अतिक्रमण के चलते बढ़ रहा है भूस्खलन का खतरा

सरकारी बंजर जमीन, जोकि एक संरक्षित वन है, उसपर अवैध और अनधिकृत गतिविधियों के बारे में एनजीटी के समक्ष एक हलफनामा दायर किया गया है।

मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का है। जिसपर बढ़ते अतिक्रमण के चलते बारिश के पानी में रूकावट पैदा हो गई है। जिस कारण भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। जिससे रोड, सामाजिक संपत्ति और लोगों की संपत्ति को खतरा पैदा हो गया है इसके साथ ही सुंदर सिंह द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनके अनुसार यह स्पष्ट रूप से सरकारी विभाग विशेष रूप से वन विभाग की लापरवाही को दर्शाता है।

ऑस्ट्रेलियाई समुद्री तट पर फंसी सैकड़ों पायलट व्हेलों की मौत

एजेंसियां

ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट तस्मानिया में मार्की हार्बर पर फंसी करीब ***460 पायलट व्हेलों के पॉड में से ज्यादातर की मौत हो गई. छिछले तटों की ओर आकर फंसी केवल 108 व्हेलों की जान बचाई जा सकी।*** वहीं 300 से ज्यादा पायलट ह्वेलों को नहीं बचाया जा सका।

ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में सैकड़ों की तादाद में फंसी कुछ ही पायलट व्हेलों को बचाने में सफलता मिली।

दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में मार्की हार्बर के पास के छिछले पानी में करीब 460 पायलट व्हेलों का समूह आ फंसा था. तमाम प्रयासों के बावजूद उनमें से केवल 108 व्हेलों को बचाया जा सका. इस पॉड यानि पायलट व्हेलों के समूह के ज्यादातर सदस्य हार्बर के छिछले पानी में थीं जबकि कुछ गहरे पानी की ओर बढ़ने में कामयाब हो गई थीं. पायलट व्हेलें महासागरीय डॉल्फिन की एक किस्म होती हैं, जिसके सदस्य 7 मीटर (23 फीट) तक लंबे और 3 टन तक भारी हो सकते हैं।

बचाव अभियान

कम गहरे पानी में जाकर फंस गई व्हेलों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके लिए व्हेलों के पास भारी मात्रा में ठंडा पानी ले जाकर उन्हें एक झूले जैसी चीज पर टांगने की कोशिश की जाती है और इस तरह उन्हें धीरे धीरे गहरे पानी की ओर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। तस्मानिया के पार्क्स और वाल्डलाइफ सर्विस के क्षेत्रीय प्रबंधक निक डेका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, "हमने एक ऐसा तरीका आजमाने पर सहमति बनाई, जिसमें पहले एक झूले जैसी चीज को व्हेल के नीचे से गुजारा जाता है जो नाव से जुड़ा होता है. इसके अलावा गहरे पानी में भी क्रू मौजूद होता है।

सबकी भागीदारी

बचाव अभियान से जुड़े 60 से भी अधिक लोगों में स्थानीय मछुआरे, स्वयंसेवी और पेशेवर शामिल हैं. इस समय यहां पानी इतना ठंडा है कि खास वेटसूट पहन कर काम करने के बावजूद

सभी बचावकर्मी छोटी शिफ्टों में काम कर रहे हैं ताकि ज्यादा ठंड लगने के कारण उन्हें हाइपोथर्मिया नाम की स्वास्थ्य परेशानी का सामना ना करना पड़े। सरकारी संरक्षण एजेंसी में काम करने वाले वन्यजीव जीवविज्ञानी क्रिस कार्लयन ने कहा कि हम बड़े और संकट में पड़े जानवरों से निपट रहे हैं। इसमें कई कई दिन का समय लग जाता है और भावनात्मक रूप से भी यह काफी कठिन है। कार्लयन कहते हैं कि यह एक "प्राकृतिक घटना है इसलिए इसमें कुछ जानवरों की जान जा सकती है। हम केवल ज्यादा से ज्यादा को बचाने पर फोकस कर सकते हैं।

बीच पर क्यों जाती हैं व्हेलें

वैज्ञानिकों को अब तक नहीं पता चला है कि हमेशा समूह में यात्रा करने वाली पायलट व्हेलें कभी कभी समुद्र तटों की ओर क्यों बढ़ जाती हैं. स्तनधारियों की यह प्रजाति आम तौर पर किसी नेता के नेतृत्व में चलती है और अपने पॉड में किसी के घायल हो जाने या परेशानी में पड़ने पर उसे अकेला नहीं छोड़तीं और उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती हैं. इस इलाके में अकसर व्हेलों को समुद्री तटों पर देखा जाता रहा है. लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इन्हें कभी नहीं देखा गया था. इसके पहले सन 2009 में तस्मानिया के पास करीब 200 भटकी हुई व्हेलें दिखी थीं. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास के इलाकों में कई किस्म की व्हेलें मिलती हैं. हर साल ये व्हेलें छोटे समूहों से लेकर 1,000 जैसी बड़ी तादाद में पॉड बना कर दूर दूर के पानी में माइग्रेट करती हैं. 2018 में भी न्यूजीलैंड में इसी तरह फंसने से एक ही हफ्ते के भीतर 200 से अधिक पायलट व्हेलों की मौत हो गई थी.

एनजीटी ने दिया रामबन नगरपालिका समिति को जुर्माना भरने का निर्देश

एनजीटी ने 22 सितंबर को रामबन नगरपालिका समिति को जुर्माने की रकम को दो किश्तों में भरने का निर्देश दिया है। इस जुर्माने को छह महीने के भीतर जमा करना है। इसे जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नगरपालिका को पर्यावरण सम्बन्धी मानदंडों पर सतर्कता बरतने की भी चेतावनी दी है।इससे पहले जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने आदेश के माध्यम से 8 जुलाई को मुआवजे की राशि का आकलन किया था। जिसमें कचरे की गलत तरीके से डंपिंग को रोकने में असमर्थ रहने पर नगरपालिका समिति के खिलाफ जुर्माना लगाया था। एनजीटी ने अपने फैसले में कहा कि यह निर्विवाद है कि पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है उसके लिए स्थानीय निकाय जिम्मेवार है, क्योंकि उसने अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन सही से नहीं किया था। हालांकि, कोरोनोवायरस महामारी और नगरपालिका समिति द्वारा रखी गई वित्तीय बाधाओं की दलील के संबंध में कोर्ट ने मुआवजे की राशि को 50 फीसदी तक कम कर दिया है।

रेवाड़ी में तालाब पर अवैध अतिक्रमण और कचरे की डंपिंग का मामला

रेवाड़ी में तालाब पर अवैध अतिक्रमण और कचरे की डंपिंग का मामला 22 सितंबर को एनजीटी के सामने आया है। मामला हरियाणा के रेवाड़ी जिले के प्रताप पुर इलाके का है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट भी दायर की गई है, जिस-के अनुसार 20 नवंबर, 2019 को नगरपालिका परिषद के प्रतिनिधियों ने साइट का निरीक्षण किया था। जिसके आधार पर उसकी रोकथाम की कार्रवाई की गई थी और नगरपालिका परिषद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। एनजीटी ने रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया है कि पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों को ध्यान में रखकर आगे की कार्यवाही की जाए। साथ ही पर्यावरण से जुड़े नियमों की अनदेखी न हो इसलिए उसपर नजर रखी जाए।

तीनों कृषि विधेयकों से आखिर किसे होने वाला है फायदा?

20 सितंबर 2020 को राज्यसभा ने तीन कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी है। ये तीनों विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएंगे। जहां सरकार लगातार दावे कर रही है कि यह बिल किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, वहीं कई किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर इन तीन विधेयकों में क्या है? प्रस्तुत है इस विषय पर कृषि अर्थशास्त्री देविन्दर शर्मा के विचार

जो कानून बनकर आ रहे है। उसके पीछे सरकार का मकसद है कि किसान की आमदनी बढ़े, उनकी समृद्धि बढ़े। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आए, नई टेक्नोलॉजी आए। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अधिक से अधिक निवेश करे। सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र खेती में उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक में न केवल निवेश बढ़ाए, बल्कि नई तकनीक का भी इस्तेमाल करे। यह दावा किया जा रहा है कि इससे किसानों को अपनी उपज की ऊंची कीमत मिलेगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी। हम तो चाहेंगे कि यह सच हो, क्योंकि किसान भी सालों से इसी बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी आमदनी बढ़े और उनकी उपज की सही कीमत उन्हें मिले।

लेकिन यह एक बड़ी चुनौती है। अब तक यह बताया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर ही किसान को सही कीमत दे सकता है और किसान को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इसके दो तीन पहलुओं पर बात करनी जरूरी है। यह बात किसानों को भी समझनी चाहिए, एकेडमिशन हो या छात्र हो, बल्कि देश के हर नागरिक को भी समझनी चाहिए और खासकर नीतियां बनाने वाले लोगों को भी समझनी चाहिए।

पहले बिल कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020 की बात करते हैं। अगर हम दुनिया भर में देखें तो ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि मार्केट रिफॉर्म्स की वजह से किसानों को फायदा हुआ हो। क्योंकि अमेरिका और यूरोप में कई दशकों पहले ओपन मार्केट के लिए कृषि उत्पादों को खोल दिया गया था। और अगर ओपन मार्केट इतनी अच्छी होती और किसानों को फायदा दिया होता तो अमीर यानी विकसित देश अपने यहां कृषि को जीवित रखने के लिए भारी सब्सिडी क्यों देते हैं? 2018 की बात करें तो अमेरिका और यूरोप में 246 बिलियन डॉलर की सब्सिडी किसानों को दी गई। अकेले यूरोप में देखें तो 100 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी गई। जिसमें तकरीबन 50 फीसदी डायरेक्ट इनकम सपोर्ट थी। और अमेरिका की बात की जाए तो अध्ययन बताते हैं कि अमेरिका के एक किसान को औसतन लगभग 60 हजार डॉलर सालाना सब्सिडी दी जाती है। यह सिर्फ औसत है, जबकि वैसे देखा जाए तो यह इससे भी अधिक हो सकती है। इसके बावजूद भी अमेरिका के किसान बैंकों के दिवालिया हैं, किसानों पर बैंकों की दिवालिया राशि लगभग 425 बिलियन डॉलर है। अगर मार्केट इतनी अच्छी होती तो अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में आत्महत्याओं की दर नहीं बढ़ती। यहां शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में 45 फीसदी अधिक आत्महत्याएं होती हैं। दुनिया भर के अखबार बताते हैं कि अमेरिका में किस तरह धीरे-धीरे कृषि खत्म होती जा रही है। अमेरिका में ओपन मार्केट के 6-7 दशक बाद कृषि पर निर्भर आबादी घटकर 1.5 फीसदी रह गई है तो हमें इस पर दोबारा चिंतन करना चाहिए कि क्या वो मॉडल, जो अमेरिका और यूरोप में फेल हो चुका है, भारत के लिए उपयोगी रहेगा और भारत के किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा?

भारत में भी ओपन मार्केट का एक प्रयोग किया जा चुका है। 2006 में बिहार में एपीएमसी (एग्री प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) भंग कर दी गई और कमेटी की मंडियों को हटा दिया गया। कहा गया कि इससे प्राइवेट इंवेस्टमेंट आएगी। पब्लिक सेक्टर बिल्कुल हट जाएगा। प्राइवेट मंडिया आएंगी और उससे प्राइस रिक्वरी होगी । प्राइस रिक्वरी का मतलब है कि किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा।उस समय यह कहा जा रहा था कि बिहार में क्रांति आ जाएगी और बिहार पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। यह भी कहा गया कि अब पंजाब भूल जाएंगे और कृषि क्षेत्र के लिए बिहार देश का एक नया मॉडल साबित होगा। 14 साल हो चुके हैं, क्या ऐसा हुआ? जिन अर्थशास्त्रियों ने उस समय इस बात को प्रमोट किया था। वो आज आकर क्यों नहीं बताते कि इस रिफॉर्म से बिहार को क्या फायदा पहुंचा।

अब बात करते हैं दूसरे बिल कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 की किसानों का कहना है कि अगर कांट्रेक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया तो वे कंपनियों के अधीन हो जाएंगे और अपनी ही जमीन पर वे गुलामों की तरह काम करेंगे। यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन मेरा यह कहना है कि किसानों को यह कहा जा रहा है कि कांट्रेक्ट पांच साल के लिए होगा और एडवांस में ही किसान को यह बता दिया जाएगा कि उसे इनकम कितने मिलेगी। यह दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर किसान को एमएसपी से कम कीमत मिलती है तो इससे किसान का क्या फायदा होगा? इसलिए इस कानून में यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान को एमएसपी से कम कीमत नहीं दी जाएगी। लेकिन इससे हट कर देखा जाए तो हमारे देश में एक नए प्रयोग करने का सही समय आ गया है। मैं बहुत साल से यह बात कहता रहा हूं कि अगर हम दूध में कॉपरेटिव का सिस्टम ला सकते हैं और वह मॉडल पूरी तरह से सफल रहता है तो क्यों नहीं हम खाद्यान्न, फल, सब्जियों में एक कॉपरेटिव सिस्टम लेकर आ सकते हैं। लेकिन हमारे देश में तो कॉपरेटिव्स को तोड़ने की कोशिश की जाती रही है। इस बात से वर्गीज कूरियन बहुत नाराज थे। यह हम भी जानते हैं कि इन्हें क्यों तोड़ा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कॉपरेटिव को बढ़ावा देना चाहिए। इन कॉपरेटिव्स पर किसानों का नियंत्रण होगा। उन्हें किसी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना होगा। अगर किसान इकट्ठा होकर काम करते हैं तो किसान अपनी उपज का मोल भाव करने की भी स्थिति में होंगे। और अगर इसे एमएसपी के साथ लिंक कर दिया जाता है तो ये कॉपरेटिव देश को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। वर्गीज कूरियन ने दूध के संकट से निकलने का रास्ता दिखाया था, इसी तरह खेती के संकट से भी कॉपरेटिव्स निकाल सकती हैं। बेशक सरकार इन दिनों फार्मर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन (एफपीओ) बनाने की बात कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि कॉपरेटिव-कॉपरेटिव ही हैं। एफपीओ में भी बहुत सारी खामियां हैं। इस तरह की भी शिकायतें हैं कि आढ़तियों ने ही एफपीओ बना लिए हैं। कई सरकारी अधिकारियों ने एफपीओ बना लिए हैं। लेकिन अगर एफपीओ भी किसान को उचित दाम (एमएसपी) नहीं दिला पाता तो उनका कोई फायदा नहीं। यह कहा जाता है कि एफपीओ किसान को ज्यादा दाम देंगे, लेकिन ज्यादा का मतलब क्या?अगर ये एफपीओ बाजार में मिल रहे कम दाम में कुछ बढ़ा कर किसान को देते हैं, लेकिन तब भी एमएसपी से कम कीमत किसान को मिलती है तो किसान को नुकसान होना तय है।

तीसरा बिल है, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जैसे ही मैं इस बिल के बारे में सोचता हूं तो मुझे मदर इंडिया फिल्म की याद आ जाती है। यह फिल्म देखने के बाद से मैं यह मानता था कि कन्हैया लाल एक विलेन थे। लेकिन अब जब यह नया कानून आया है तो मुझे लगता है कि कन्हैया लाल की क्या गलती थी। वो भी तो होल्डिंग ही करता था। अगर यह कानून पहले ही लागू हो जाता था तो हम कन्हैया लाल को विलेन नहीं मानते। बल्कि उन्हें आर्थिक प्रगति का पर्याय मानते। अब देखिए, अगर ये बड़े-बड़े रिटेलर जैसे वालमार्ट, टेस्को आदि अमेरिका के किसानों को सही कीमत दे रहे होते तो अमेरिका का किसान कर्ज में क्यों डूबता या खेती क्यों छोड़ता? क्या हम यह कह सकते हैं कि भारतीय कंपनियों का हृदय परिवर्तन हो गया है या उन्होंने नया हृदय लगा लिया है। ऐसा मुझे तो नहीं दिखता। लेकिन यह कानून लागू होने के बाद किसान को तो दाम नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब किसी एक बड़ी कंपनी का एकाधिकार हो जाएगा तो वह अपनी मनमानी कीमत पर कृषि उपज खरीदेगी, जिसका नुकसान किसान को झेलना पड़ेगा, लेकिन किसान के अलावा यदि आम उपभोक्ता या मिडल क्लास पर इसका असर पड़ेगा, जो कि पड़ना तय है, क्योंकि बड़ी कंपनियां जितना मर्जी उपज खरीदकर होल्ड कर लेंगे तो महंगाई बढ़ना तय है। ऐसे में मिडल क्लास अब किसान को दोष नहीं दे सकेगा। कुछ ऐसा ही इन दिनों कर्नाटक में हो रहा है, जिसकी वजह से प्याज के दाम बढ़े हुए हैं। यहां एक बात जानना जरूरी है कि 2005 में सरकार एपीएमसी एक्ट में एक संशोधन लेकर आई थी। जिसमें बड़ी कंपनियों को यह छूट दी गई थी कि वे सीधे किसान के पास जाकर उपज खरीद सकते हैं। कंपनियों से एपीएसी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तब कई बड़ी-बड़ी कंपनियों ने जाकर किसानों से गेहूं खरीदा। उन्होंने इतना खरीद लिया कि सरकार को पीडीएस के तहत राशन देने की दिक्कत हो गई। तब सरकार के पूछने पर भी किसी कंपनी ने स्टॉक के बारे में नहीं बताया। तब सरकार को 5 मिलियन टन गेहूं आयात करना पड़ा था, जो कि हरित क्रांति के बाद का सबसे बड़ा आयात था। बल्कि इसकी जो कीमत दी गई, वो किसानों को दी जाने वाली कीमत से लगभग दोगुनी थी। ***ये लेखक के अपने विचार हैं***

सीसीएल में पेंशन अदालत :17 लाभार्थियों को 'पीपीओ' प्रदान किया गया

रांची : सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस, रांची स्थित'विचार मंच'में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये23 सितंबर को 'पेंशन अदालत'का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीसीएल के लगभग 150 सेवानिवृत कर्मी उपस्थित थे। पेंशन अदालत में सीएमपीएफ पेंशनर अपनी समस्याओं को सीएमपीएफ एवं सीसीएल प्रबंधन के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याओं को रखा। इस अवसर पर सीएमपीएफ कार्यालय (रिजन 1) सहायक आयुक्त आर.के. सिन्हा एवं महाप्रबंधक (सामाजिक सुरक्षा/पेंशन) यू.पी. नारायण एवं महाप्रबंधक (पी.एए-ड.आई.आर.) उमेश सिंह ने पेंशनरों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त किया कि शीघ्र ही निदान किया जायेगा।

पेंशन अदालत में लगभग 66 ग्रिवांशेस प्राप्त हुआ है जिसे सीसीएल प्रबंधन एवं सीएमपीएफ कार्यालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शीघ्राशीघ्र निष्पादन किया जायेगा। पेंशनर अदालत के दौरान 17 लाभार्थियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) निर्गत किया गया, जिसका पेंशन होल्डर्स या उनके प्रतिनिधि ने आदेश की प्रति प्राप्त किया। साथ ही सीएमपीएफ कार्यालय की ओर से जानकारी दी गयी कि अन्य 8 लाभार्थियों को पीपीओ शीघ्र दिया जायेगा और अन्य 18 लाभार्थियों का पेंशन की राशि का निर्धारण प्रक्रिया अंतिम चरण में है और उन्हें भी शीघ्र पीपीओ दे दिया जायेगा।

सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद ने पेंशन अदालत के सफल आयोजन के लिए पेंशन विभाग को साधुवाद दिया और कर्मियों के सामाजिक सुरक्षा हेतु इस प्रकार की पहल को नियमित रूप से आयोजित करने के लिए कहा।

निदेशक (कार्मिक) विनय रंजनकहा कि पेंशन विभाग कर्मियों के पेंशन संबंधी लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु सीसीएल के सभी क्षेत्रों में पेंशन अदालत का आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग सेवानिवृत कर्मियों के समस्याओं एवं शिकायतों के शिघ्रातिशीघ्र निपटारे के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हम कई नयी पहल कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक (सामाजिक सुरक्षा/पेंशन) श्रीमती अर्चना सिंन्हा, श्रीमती कविता कुमारी एवं अन्य उपस्थित थे।

रेल सुरक्षा बल के 36 वें स्थापना दिवस के पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन

रांची: रेल सुरक्षा बल के 36 वें "स्थापना दिवस" के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन रांची रेल मंडल पर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत दिनांक 26.09.2020 को रेलवे सुरक्षा बल थाना हटिया, रांची, मुरी, सुईसा एवं बानो में एक विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया । जिसमे रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं रेलवे सुरक्षा बल सदस्यों को योग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, साथ ही साथ कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु युक्तियों भी बताई गई। योग शिविर का आयोजन के उपरांत रांची मंडल के सभी रेलवे सुरक्षा बल इकाइयों में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए ।

उपरोक्त कार्यक्रम मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव के कुशल नेतृत्व में किया गया। रेल सुरक्षा बल रांची के "नन्हे फरिश्ते" टीम द्वारा नामकुम के रहने वाला एक लड़का अमनजीत कुमार जो अपने घर से निकल गया था उसे दिनांक 25.09.2020 को रात 08:00 बजे हटिया रेलवे स्टेशन पर आ गया था । "नन्हे फरिश्ते" टीम के द्वारा इस बच्चे को सुरक्षित उसके अभिभावक को सौंप दिया गया।

सीसीएल ने दिव्यांगों के बीच नि:शुल्क कृत्रिम उपकरण एवं ट्रायसाईकल का किया वितरण

संवाददाता

रांची : सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड(सीसीएल) द्वारा आयोजित वितरण समारोह में विगत 23 एवं 24 सितम्बर को रामगढ़ जिले मेंक्रमशः रामगढ़ और मांडू ब्लॉक में 137 दिव्यांगों के बीच नि:शुल्क कृत्रिम उपकरण एवं ट्रायसाईकल आदि का वितरण किया गया। इस वितरण समारोह में जिला प्रशासन एवं सीसीएल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दिव्यांगों के बीच विभिन्न उपकरण जैसे बैटरीयुक्तट्राई-साईकल, व्हीलचेयर, क्रच, स्मार्टकेन आदि वितरित किए गए।

सीसीएल के निदेशक (कार्मिक) विनय रंजन ने कहा कि सीएमडी पी.एम. प्रसाद के नेतृत्व में कंपनी समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह के वितरण शिविरों का आयोजन आगे भी समय-समय पर होता रहेगा।

सीआरजेड अधिसूचना का उल्लंघन नहीं करती है: लार्सन एंड टुब्रो

एजेंसियां : मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक वनस्पतियों और जीवों पर खराब प्रभाव नहीं डालेगा। लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) लिमिटेड परियोजना के अधिवक्ता ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। आसपास निर्माण के कार्य से वहां की वनस्पतियां और जीव प्रभावित नहीं हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) द्वारा जरूरी तौर पर सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया था। यह एल एंड टी द्वारा 19 सितंबर, 2020 के हलफनामे में कहा गया था कि कंपनी ने एमटीएचएल परियोजना की स्थिति और पर्यावरणीय प्रभाव शमन उपायों की स्थिति निर्धारित की है। एमटीईएल और 25 जनवरी 2016 को तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना 2011 के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई स्वीकृति पर दिलीप बी. नेवतिया द्वारा अपील की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है 2011 की सीआरजेड अधिसूचना और 2006 पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना दोनों का उद्देश्य विकास को रोकना नहीं है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विकास करना है। पर्यावरण को होने वाले किसी भी नुकसान को कम करना है। 2011 के सीआरजेड अधिसूचना के खंड 3 (iv) के अनुसार सीआरजेड क्षेत्रों में एक ट्रांस-हार्बर समुद्री लिंक का निर्माण अनुमन्य था। इसके अलावा, खंड 8 (i) प्रदान करता है कि सीआरजेड की विभिन्न श्रेणियों में विकास या निर्माण गतिविधियों को संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (सीजेडएमए) द्वारा नियमित किया जाएगा। प्रोजेक्ट के जनरल कंसल्टेंट ने 15 जनवरी को एल एंड टी को एक पत्र भेजा था जिसमें सीआरजेड मंजूरी में निर्धारित शर्तों के अनुपालन का ब्यौरा देते हुए एक जांच-सूची दी गई थी। इनमें से एक शर्त 'प्रतिपूरक मैंग्रोव बहाली' की थी। मुख्य वन संरक्षक को 200 हेक्टेयर से अधिक में मैंग्रोव वन लगाने का काम सौंपा गया था। इन उपायों के लिए मुख्य वन संरक्षक को परियोजना अधिवक्ता द्वारा लगभग 5.05 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पालघर और मुंबई उपनगरीय क्षेत्रों में मैंग्रोव सेल ने 105 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जिले के पदाधिकारियों के साथ की बैठक

गढवा : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री, झारखंड सरकार मिथिलेश ठाकुर की अध्यक्षता में 25 सितं. को जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने जिले के विभिन्न विभागों यथा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, वन विभाग समेत अन्य विभागों की कार्य प्रगति का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में थाना बनवाने से हो, घटित हो रहे क्राइम पर काबू पाया जा सकेगा। उन्होंने शिक्षा विभाग से समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि दसवीं तक के विद्यालयों को प्लस टू करवाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि अब तक 23 विद्यालयों का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है शेष का प्रस्ताव प्राप्त होते ही इसे दिनांक 25 अक्टूबर तक विभाग को भेज दिया जाएगा। वहीं नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण व पुराने आंगनवाड़ी केंद्रों के जीर्णोद्धार के संबंध में बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 494 आंगनवाड़ी केंद्र भवन विहीन है, जो कि किराए के मकान में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एससीए योजना के तहत 50 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाना है वहीं उक्त योजना के तहत ही 50 आंगनबाड़ी केंद्रों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। इसपर माननीय मंत्री ने कहा कि जांच उपरांत शेष बचे आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव को विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

इसके अलावा उन्होंने मनरेगा के तहत ग्रामीण सड़कों की मरम्मत पर भी चर्चा की तथा कहा कि जिले के सभी पथों को मोटोरेबल (चलने योग्य) बनाया जाए। बैठक में औद्योगिक पार्क के निर्माण से संबंधित मामले पर भी चर्चा करते हुए संबंधित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के चामा में 25 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क निर्माण हेतु प्रस्ताव अपर समाहर्ता गढ़वा द्वारा भेजा जा चुका है।

प्रकृति नहीं, इंसान की देन है ब्रॉयलर चिकन

एजेंसियां

हमने बॉयलर चिकन के जीन को बढ़लकर उनके चयापचय को नियंत्रित करने वाले रिसेप्टर को म्यूटेट कर दिया है

क्या आपको पता है कि आपके पसंदीदा बॉयलर चिकन के शरीर का आकार, हड्डियों की बनावट और आनुवांशिकी उसके पूर्वज मुर्गों या जंगली मुर्गों से मेल नहीं खाते? यह जानने के बाद आपका अगला सवाल हो सकता है, इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ब्रिटेन में लीसेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस सवाल पर वर्षों तक गहराई से शोध किया। दिसंबर, 2018 में जब उन्होंने अपने निष्कर्षों के बारे में लिखा, तो दुनिया एक ऐसी वास्तविकता से रूबरू हुई जिसकी आशंका हमें लंबे समय से थी। उनका निष्कर्ष था, ''बॉयलर चिकन पूरी तरह से मानव निर्मित है।'' शोधकर्ताओं में से एक एलिसन फोस्टर ने कहा, ''मुर्गों को पालतू बनाए जाने के बाद से उनकी कई अजीब और सुंदर नस्लें आई हैं लेकिन बॉयलर शायद इनका सबसे चरम रूप है।

यह अध्ययन बॉयलर चिकन की शारीरिक संरचना का पता लगाने के लिए नहीं था। इसके पीछे की मुख्य वजह एंथ्रोपोसीन नामक एक नए मानव युग के आगमन की पड़ताल करना था। हमारी धरती पर मौजूदा वक्त में 2,300 करोड़ बॉयलर चिकन मानवों का भोजन बनने के लिए तैयार हैं। इस तरह ये चिकन भूमि पर पाए जाने वाले कशेरुकी यानी रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की सबसे बड़ी प्रजाति है।

शोधकर्ता ऐसी चीज की तलाश कर रहे थे, जिसमें मानव हस्तक्षेप के भारी संकेत हों। इसका उपयोग वैज्ञानिक रूप से यह इंगित करने के लिए किया जाएगा कि मनुष्यों ने पृथ्वी पर जीवन और पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है। यह बदले में नए मानव युग की घोषणा करने के लिए एक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाएगा। शोधकर्ताओं ने कहा, ''आधुनिक चिकन अब अपने पूर्वजों से इतना बदल गया है कि इसकी विशिष्ट हड्डियां निस्संदेह उस समय के जीवाश्म संकेत बन जाएंगी जब मनुष्य ने ग्रह पर शासन किया था।

रोमन काल के मुर्गों के साथ बॉयलर चिकन की हड्डियों की तुलना करना इस शोध में शामिल था। शोधकर्ताओं ने दोनों मुर्गों की हड्डियों में शायद ही कोई समानता पाई। बॉयलर चिकन अपने मध्यकालीन रिश्तेदार की तुलना में दो गुना बड़ा है। इसका कंकाल तो बड़ा होता ही है, साथ ही हड्डियों की रासायनिक बनावट भी अलग होती है। इसके अलावा इनमें आनुवंशिक विविधता की भी काफी कमी है। बॉयलर चिकन के वैज्ञानिक मूल्यांकन से पता चला कि उनका आहार भी लगभग समान

होता है। ये सब सिर्फ एक उद्देश्य से पाले जाते हैं और वह है मानव उपभोग के लिए मांस उपलब्ध कराना।

शोधकर्ताओं का निष्कर्ष था कि ''आधुनिक चिकन के वर्तमान रूप के लिए केवल और केवल मानव हस्तक्षेप जिम्मेदार है। हमने उनके जीन को बदलकर उनके चयापचय को नियंत्रित करने वाले रिसेप्टर (ग्राही) को म्यूटेट (परिवर्तित होना) कर दिया है जिसके कारण वे हमेशा भूखे रहते हैं। इस कारण वे ज्यादा से ज्यादा खाते हैं और उनके आकार में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, उनका पूरा जीवन चक्र मानव प्रौद्योगिकी द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरण के लिए, मुर्गियां जिस कारखाने में अपने अंडों से निकलती हैं, वहां का तापमान और आर्द्रता कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। पहले ही दिन से उन्हें बिजली की रोशनी में रखा जाता है ताकि उनके भोजन के घंटे बढ़ाए जा सकें। उन्हें मारा भी मशीनों की ही मदद से जाता है। इससे एक घंटे में हजारों मुर्गों का मांस तैयार हो जाता है।

फोटो न्यूज

झारखंड के पर्यावरणविद् और भूगर्भशास्त्री नितिश सर के फेसबुक वाल से

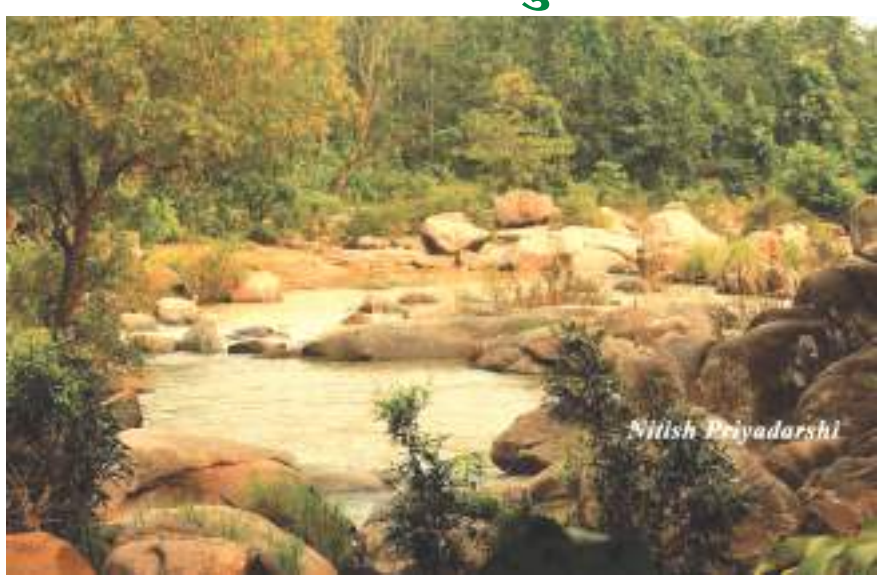

ये जगह है रांची से महज २० किलोमीटर दूर कालामाटी का। घने जंगलो से होके बहती छोटी छोटी नदियां और झरने , दूर दूर तक जंगल के बीच फैले हरे भरे खेत। जंगल से बहती नदियों की आवाज, झींगुर और चिड़ियों की आवाज साथ में ठंडी हवाएं मन को शांत कर जाती है। दूर दूर तक कोई मानव जनित आवाज नहीं सिर्फ जंगल की आवाज। आपकी सारी चिंता कुछ समय के लिए गायब। अगर अपने मन एवं शरीर को स्वस्थ रखना है तो महीने में एक बार जंगल का आनंद जरूर लें। इसके लिए जरूरी है की हम ऐसे जगहों को उजड़ने से बचाएं। हम जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना ही अस्पतालों से दूर होंगे।

केला है एक लाजवाब सुपर फूड

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

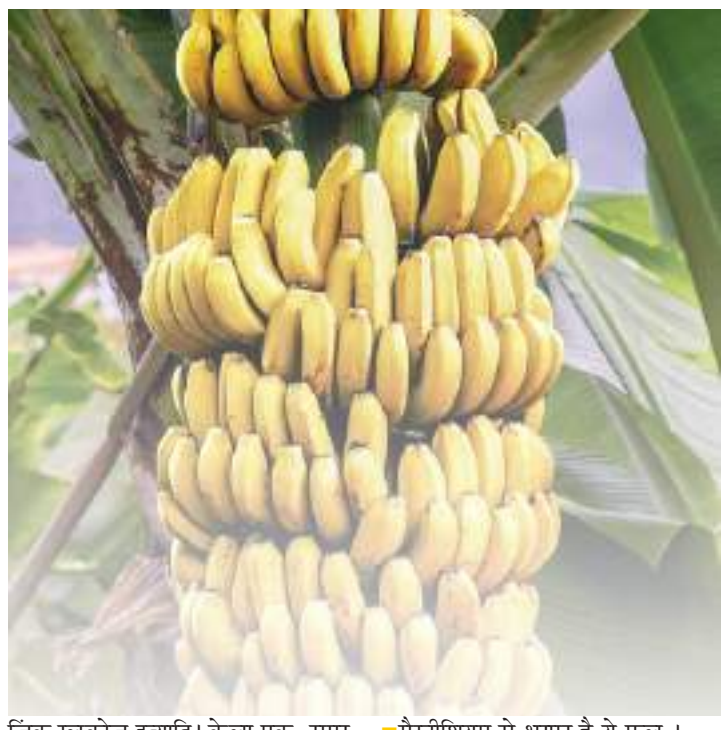

केला एक ऐसा फल ,जो हर मौसम में मिलता है और काफी किफायती भी है।सबसे अच्छी बात ये है कि भारत केले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है तो यही कारण है कि हमें अच्छे गुणवत्ता वाला केला यहाँ मिलता है।

कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि केला खाने से वज़न बढता है लेकिन ये एक कल्पित कथा है, अगर सही समय और सही मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो इसके कई फायदे हैं।

कोई चीज अगर अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कि जाये तो वो नुकसान करती है वैसे ही अगर केले का अत्यधिक मात्रा मे सेवन किया जाए तो ये वज़न बढ़ने का कारण हो सकता है।

केले में कई पोषक तत्व हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट,विटामिन ए,विटामिन सी, जिंक,ग्लूकोज इत्यादि। केला एक सुपर फूड है। जिसके बहुत सारे फायदे हैं तो आइये देखते हैं इसके लाभ।

- केले में आयरन होता है इसका सेवन एनीमिया जैसे बिमारी में सहायक है।
- मैग्नीशियम से भरपूर है ये फल ।
- पाचन क्रिया में सुधार होता है क्योंकि केले में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है।
- प्री वर्कआउट फूड के लिए केला बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये ऊर्जा से भरपूर है।
- प्रतिदिन केला का सेवन करने से डिप्रेशन मे भी राहत मिलता है और हम काफी अच्छा महसूस करते हैं।
- कब्ज, गैस या पेट सम्बन्धी कोई और समस्या हो तो केले का सेवन करने से काफी राहत मिलता है। ये आंतों की सफाई करकेउन्हें भी स्वस्थ रखता है।
- शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ता है और चुस्त और फुर्तीला रखने में सहायक होता है।
- चेहरे पर भी चमक लाता है, केले को शहद के साथ चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ कम होने लगती है और त्वचा में कसावट आता है।
- शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने के साथ साथ ये दिमाग को भी स्वस्थ रखता है।
- कच्चा केला भी बहुत ही लाभदायक है, डायबीटीस जैसे बिमारी में काफी फायदेमंद होता है।

केला जो कि एक गुणकारी और किफायती फल है इसे अपने आहार में शामिल करना चाहिए पर याद रहे बहुत ज्यादा इसका सेवन भी उचित नहीं है।

हमसे जुड़े.रहने के लिए (इंस्टाग्राम)
instagram **पर फ़ॉलो करें**
ritusinghfitness.

मणिपुर में 2,282 जैव विविधता प्रबंधन समितियां प्रस्तावित

मणिपुर बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने एनजीटी के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य, जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य भर में 2,282 जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन को प्रस्तावित किया गया है। जिसमें से 84 फीसदी, मतलब 1908 समितियों को पहले ही गठित किया जा चुका है, जबकि केवल 374 समितियों को गठित करना बाकी है। रिपोर्ट में जानकारी दी है कि बाकी समितियों के निर्माण में जो देरी हुई है उसके लिए मुश्किल और दुर्गम इलाके, ग्रमीणों का इनकार और कोरोनावायरस के कारण हुआ लॉकडाउन मुख्य रूप से जिम्मेवार है।

Manipur Biodiversity Board

आसाम में मचकी ओआईएल परियोजना जांच के घेरे में

एजेंसियां

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 17 सितंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह ऑइल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा असम के तिनसुकिया जिले में मचकी, मचकी एक्सटेंशन, बागजान और तिनसुकिया एक्सटेंशन पीएमएलएस को कवर करते हुए प्रस्तावित ऑनशोर तेल और गैस विकास ड्रिलिंग और उत्पादन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। प्रस्तावित परियोजना एक पारिस्थितिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील और नाजुक क्षेत्र में बताई गई है, जहां मचकी ब्लॉक डिब्रू-साइकोवा नेशनल पार्क, मगुरी-मोटापुंग आर्द्रभूमि परिसर के करीब स्थित है और यह देहिंग पटकई हाथियों के लिए आरक्षित (रिजर्व) क्षेत्र का हिस्सा है। यह आरोप लगाया गया है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 का उल्लंघन करके पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है। क्योंकि परियोजना के अधिवक्ता ने संचयी प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता के साथ-साथ पारिस्थितिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील और जैव विविधता वाले स्थान के बारे में फॉर्म -1 में जानकारी छिपाई थी। यह भी उस समृद्ध परिदृश्य में जिसमें एक राष्ट्रीय उद्यान, एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र और साथ ही एक हाथियों के लिए आरक्षित (रिजर्व) क्षेत्र भी शामिल है।

20 प्रतिशत हृदयरोगियों की मौत तंबाकू से

दुनिया भर में हृदय रोग से पीड़ित लगभग 19 लाख लोगों की मौत की एक बड़ी वजह यह है कि वे धूमपान भी करते थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और न्यूकैसल विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी एक नए संक्षिप्त विवरण के अनुसार, दुनिया भर में तंबाकू से होने वाले हृदय रोग से हर साल 19 (1.9 मिलियन) लाख लोग मर जाते हैं।

हृदय रोग से होने वाली पांच मौतों में से एक तंबाकू के कारण होती है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है, कि तंबाकू उपयोगकर्ताओं को दिल का दौरा पड़ने के सबसे अधिक आशंका है। धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान न करने वालों की तुलना में कम उम्र में हृदय संबंधी बीमारियां होने की असार अधिक हैं। दिन में बस कुछ सिगरेट, कभी-कभार धूम्रपान, या दूसरे के द्वारा किए जा रहे धूम्रपान के धुएं के संपर्क में आने से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर तंबाकू उपयोगकर्ता तुरंत धूम्रपान करना छोड़ देते हैं, तो एक साल बाद उनके हृदय रोग का खतरा 50 फीसदी तक कम हो जाएगा। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन टोबैको एक्सपर्ट ग्रुप के चेयरमैन डॉ. एडुआर्डो बियान्को ने कहा तम्बाकू और हृदय स्वास्थ्य को देखते हुए धूम्रपान छोड़ने से लाभ होता है। धुआं रहित तंबाकू प्रति वर्ष कोरोनरी हृदय रोग से लगभग 2 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार है। ई-सिगरेट भी रक्तचाप बढ़ाता है जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है।

कोरोनरी हृदय रोग क्या है?

कोरोनरी हृदय रोग (सीएचडी) एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल से बना वसा (फैट) जमा होता है और अन्य सेलुलर सामग्रियों जिन्हें सामूहिक रूप से प्लाक (पट्टिका) कहा जाता है, जो हृदय की सतह पर कोरोनरी धमनियों के अंदर जमा होता है, जिससे धमनियां सिकुड़ जाती है। इससे हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल की गंभीर क्षति या अचानक मृत्यु हो सकती है। यह प्रक्रिया अक्सर एक लंबी अवधि में धीरे-धीरे विकसित होती है। कई प्रभावित लोगों को तब पता चलता है जब समस्या गंभीर हो जाती है। इसके अलावा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से गंभीर कोविड-19 का खतरा बढ़ जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि इटली में कोविड-19 से मरने वाले लोगों में, 67 फीसदी में उच्च रक्तचाप था और स्पेन में, कोविड-19 से संक्रमित लोग 43 फीसदी हृदय रोग के साथ जी रहे थे।

डब्ल्यूएचओ ने अनुमान लगाया है कि दुनिया के कम से कम 38 करोड़ लोग धूम्रपान रहित तंबाकू उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। जिनमें से 13-15 वर्ष की आयु के 1.3 करोड़ बच्चे और 15 वर्ष और उसे अधिक आयु के 36.7 करोड़ वयस्क इसमें शामिल हैं। यद्यपि धूम्ररहित तंबाकू उपयोगकर्ताओं की सबसे बड़ी संख्या दक्षिण-पूर्व एशिया में है, लेकिन दुनिया के अन्य क्षेत्रों में तंबाकू का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। अध्ययन धूम्ररहित तंबाकू के उपयोग और एशिया में घातक और कम घातक हृदय रोग के बीच संबंध प्रदर्शित करता है।

डॉ. विनायक प्रसाद ने कहा सरकारों का दायित्व है कि वे अपने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और तंबाकू की महामारी को रोकने में मदद करें। धूम्रपान मुक्त होने से तंबाकू से संबंधित अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, जो कि वर्तमान महामारी के संदर्भ में पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

नदियों के जल में कोई खास सुधार नहीं हुआ:सीपीसीबी

एजेंसियां

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोनावायरस महामारी के प्रसार को कम करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारत की प्रमुख नदियों के पानी की गुणवत्ता में खास सुधार नहीं हुआ।

16 सितंबर, 2020 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को सौंपी गई सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च से अप्रैल के बीच देश की 19 प्रमुख नदियों के पानी की गुणवत्ता पर नजर रखी गई और इसकी तुलना की गई। एनजीटी ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसा करने को निर्देश दिया था ताकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और सेंट्रल एफ्लुएंट प्लांट के लिए कार्यान्वयन योजनाएं सुनिश्चित की जा सकें।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने ब्यास, ब्रह्मपुत्र, बैतमी व ब्राह्मणी, कावेरी, चंबल, गंगा, घग्गर, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, माही, नर्मदा, पेनर, साबरमती, सतलुज, स्वर्णरेखा, तापी और यमुना के पानी की गुणवत्ता का आकलन किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च में नदियों के पानी के कम से कम 387 और अप्रैल में 365 नमूने एकत्र किए गए। मार्च के दौरान 387 (77.26 प्रतिशत) निगरानी स्थानों में से कम से कम 299 में आउटडोर स्नान के लिए सूचीबद्ध मापदंडों का पालन किया। वहीं अप्रैल में 365 (75.89 प्रतिशत) स्थानों में से 277 में मापदंडों का अनुपालन किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग बंद होने, बाहरी स्नान और कपड़ा धोने जैसी गतिविधियों में कमी के कारण ब्राह्मणी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तापी और यमुना नदी में पानी की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। दूसरी ओर ब्यास, चंबल, सतलुज, गंगा और स्वर्णरेखा में सीवेज का बहाव अधिक होने और पानी की मात्रा कम के कारण गुणवत्ता खराब हो गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉक-डाउन का असर दिल्ली से बहने वाली यमुना के 22 किलोमीटर के हिस्से पर ज्यादा साफ झलक रहा था। हालांकि पानी की गुणवत्ता में हुआ सुधार शहर में बेमौसम बारिश का नतीजा हो सकता है। नदी के पानी की गुणवत्ता का आकलन पीएच, घुलित ऑक्सीजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और फीकल कॉलीफॉर्म के मापदंडों के आधार पर किया गया। इसके परिणामों की तुलना पर्यावरण (संरक्षण) नियमों, 1986 के तहत आउटडोर स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों से की गई थी।

तेजी से घट रही है ऊंटों की आबादी

संध्या झा

अगर राजस्थान की ही बात करें तो 2001 के मुकाबले 2007 में प्रदेश में ऊंटों की आबादी आधे के करीब आ गई

ऊंट यानी रेगिस्तान का जहाज घट रहा है। इसे बचाने के तमाम सरकारी उपाय असफल साबित होते दिख रहे हैं। अब से एक दशक पहले आबादी के लिहाज से भारतीय ऊंटों का सूडान और सोमालिया के बाद तीसरा स्थान था। लेकिन इनकी गणना के ताजा आंकड़े बताते हैं कि अब ये 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

भारत में एक कूबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। भारत में ऊंटों के बारे में इतिहासकार डॉविल्सन ने लिखा है कि ईसा से तीन हजार साल पहले आर्यों के यहां आगमन के दौरान एक कूबड़ वाले ऊंट के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन लगभग 2300 साल पहले सिकंदर के आक्रमण के समय एक कूबड़ वाले ऊंट भारत में लाए गए थे। ईसा से 3000 से 1800 साल पहले हड़प्पा संस्कृति काल में भी भारत में ऊंटों का उल्लेख मिलता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि वर्तमान में सिंध और राजस्थान के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्र में आदिकाल से एक कूबड़ वाले ऊंट थे।

रेगिस्तानी ऊंट की घटती आबादी को दिखाने के लिए कुछ आंकड़े रखना जरूरी होगा। साल 2001 में देश में ऊंटों की तादाद 10 लाख से ज्यादा थी। ध्यान रहे कि प्रदेशों में ऊंटों की गणना हर चार साल में होती है। आखिरी गणना 2011 में हुई थी लेकिन उसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं। और अगर राजस्थान की ही बात करें तो 2001 के मुकाबले 2007 में प्रदेश में ऊंटों की आबादी आधे के करीब आ गई। इस हिसाब से आज की स्थिति का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। देश में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में ही पाए जाते हैं। 2007 में 4136 लाख ऊंट यहां के रेगिस्तानी समंदर में तैरने के लिए बचे थे।

कभी खरगोश के आकार का होता था ऊंट

पृथ्वी पर विचरण करने वाले सबसे लंबे-चौड़े पशुओं में शामिल ऊंट के बारे में आज यदि यह कहा जाए कि कभी यह खरगोश जितना छोटा हुआ करता था तो किसी को सहसा विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सच है कि पोटीपोलस नामक ऊंट खरगोश जितना ही ऊंचा था। माना जाता है कि लगभग 50 हजार साल पहले विकास क्रम में ऊंट की उत्पत्ति हुई और ऊंट के कैमिलीड वर्ग का उद्भव सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में हुआ था। जंगली ऊंट अनुमानतः आटीया और डकटेला कोटि तथा टाइलोपोडा उपकोटि में आने वाले उष्ट्रवंश से ताल्लुक रखता है। प्राचीन काल में एक और दो कूबड़ वाले ऊंट पाए जाते थे।

पर्यावरण के लिये भी जरूरी हैं ऊंट

ऊंटों से किसानों को खेतों के अंदर जैविक खाद मिल जाती हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और पानी भी जहरीला नहीं होता। बदले में पशुपालकों को अपने पशुओं हेतु खेतों से फसल निकालने के बाद अनावश्यक बचे फूल-पत्ते, फलियां ओर भूसा मिल जाता है। ये काफी पौष्टिक होता है जिसे पशु बड़े चाव से खाते हैं। ऊंटों के कम होने से ये जुगलबंदी तो टूटेगी ही, साथ में मिट्टी के प्राकृतिक तरीके से होने वाला प्रबन्धन भी बिगड़ेगा।

गुजरात से लेकर दिल्ली तक विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली स्थित है। इसके एक ओर भारत का महान मरुस्थल है और दूसरी ओर दक्कन का पठार। अरावली रेगिस्तान के फैलाव को रोकती है और मॉनसून की स्थिति को निर्धारित करती है, वहीं दूसरी ओर ये जल विभाजक की भूमिका निभाती है। इसकी अपनी खास पारिस्थितिकी उसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। इसे अलग और खास बनाने में ऊंटों और घुमन्तू की भूमिका है जो वहां की जैव विविधता को फैलाने में मदद करते हैं। इससे वहां मौजूद पेड़-पौधे ओर झाड़ियों की हर वर्ष कटाई-छंटाई होती रहती है। अरावली को इन जानवरों से खाद मिलती है। वहां से प्राप्त होने वाली असंख्य जड़ी-बूटियों को ये चरवाहे अपने साथ अन्य राज्यों तक ले जाते हैं। यदि ऊंट और चरवाहे नहीं गए तो ये चक्र रुक जाएगा। तब अरावली को खाद कहां से मिलेगी और वहां मौजूद सूखी झाड़ियों को कौन हटायेगा? हमें ये देखना है कि अरावली में आग लगने की घटनाएं क्यों नहीं होतीं? अरावली केवल राजस्थान से दिल्ली के बीच ही कटा फटा है किंतु इससे पहले गुजरात से लेकर राजस्थान के अलवर तक तो ये निरन्तर फैला है। वहां मौजूद सूखी घास ओर झाड़ियां पशुपालक हर वर्ष हटाते हैं। अरावली की जैव विविधता को फैलाने में इन्हीं ऊंटों और घुमन्तू समाज का योगदान है।

देश और प्रदेश में ऊंटों की लगातार कम होती आबादी की सबसे बड़ी वजह है इस पशु का लगातार अनुपयोगी होते जाना। पहले राजस्थान के हजारों किमी के रेतीले समंदर में यातायात और जुताई वगैरह के काम में सबसे उपयोगी साधन ऊंट ही हुआ करता था। पर खेती में मशीनों के बढ़ते उपयोग की वजह से इनकी जरूरत लगातार घटती जा रही है। दूसरी ओर, विकास की तेज लहर में चारागाह भी साफ होते जा रहे हैं, जो ऊंटों के चारे के सबसे बड़े स्रोत रहे हैं। रेगिस्तान की इकोलॉजी इन पर निर्भर करती है इनकी संख्या ऐसे ही कम होने लगी तो रेगिस्तान के लिए बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।